

प्रेषक,

विजय कुमार ढौड़ियाल,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता अनुभाग:-1

देहरादून

दिनांक २२, जनवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में पैक्स मिनी बैंकों (ग्रामीण बचत केन्द्र) में जमा निक्षेपों हेतु निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-2455/नियो०/कॉरपस फण्ड/2014-15 दिनांक 12 अगस्त, 2014 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के पत्र संख्या:-318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-1055/XXVII(1)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पैक्स मिनी बैंकों (अब ग्रामीण बचत केन्द्र) में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष ₹15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निमांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-6938-43/व०ग्रा०वि०/सह०/2003-04 दिनांक 17 मार्च 2004 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अशंदान 0.30 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) अनुमन्य होगा। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) हैं, तत्काल जमा किये जाएं। योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराया जाए।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या ठीक अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम०-८ प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका

(2)

तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-10-पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-318/XXVII-1/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं संख्या-1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौड़ियाल)  
प्रभारी सचिव।

संख्या:-1020 (1) / XIV-1 / 2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त -4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आशा से,

(सुनील सिंह)  
उपसचिव।